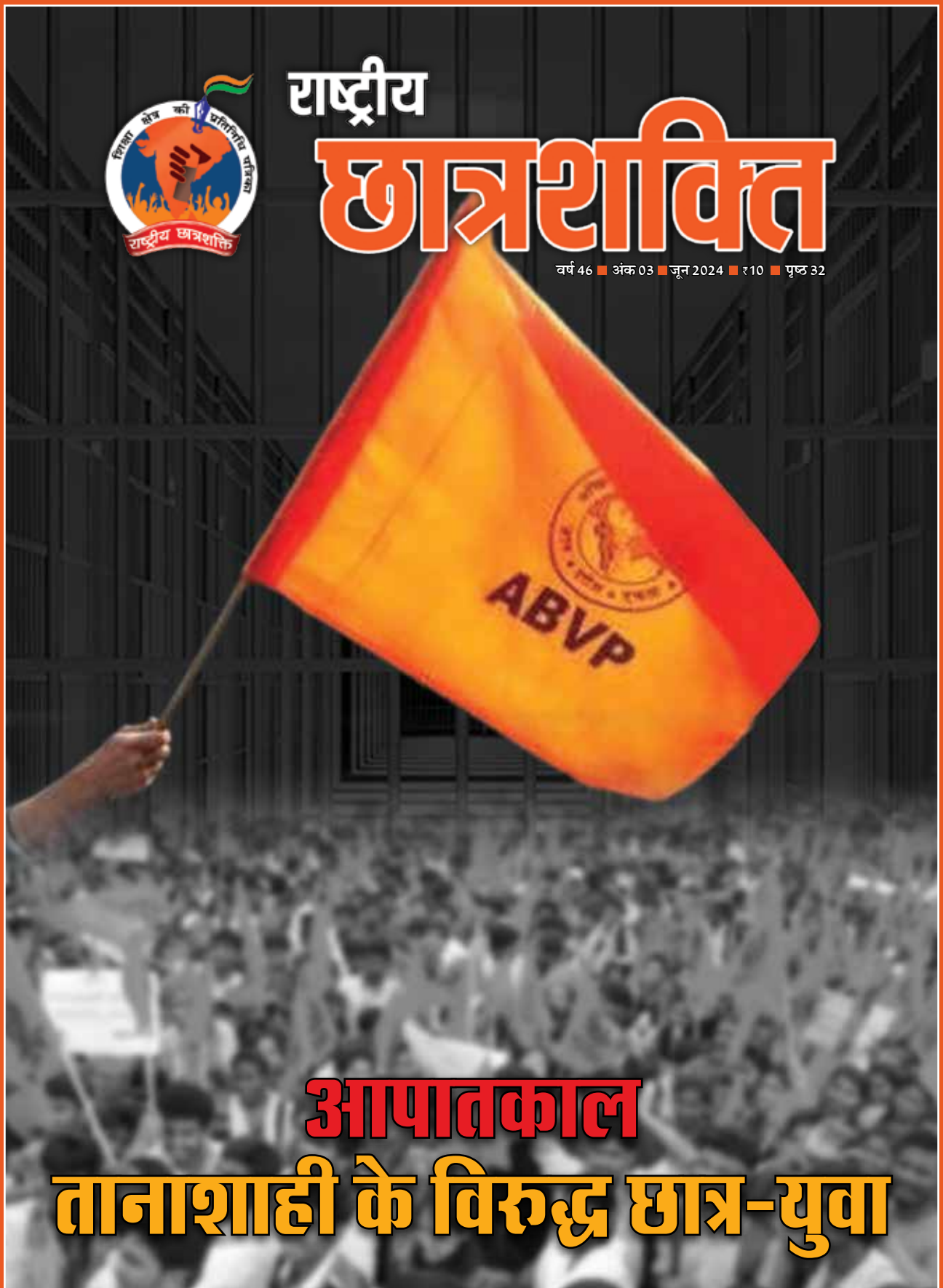

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 46 ■ अंक 03 ■ जून 2024 ■ ₹10 ■ पृष्ठ 32

आपातकाल
तानाशाही के विरुद्ध छात्र-युवा

बेंगलुरु में आयोजित सृष्टि-2024

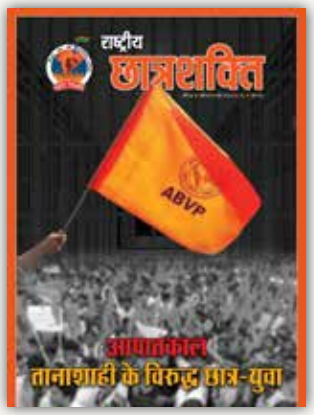

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा–क्षेत्र की प्रतिनिधि–पत्रिका

वर्ष 46, अंक 03
जून 2024

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक–मण्डल :
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नई दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110092 से मुद्रित। **संपादक** *पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेवार।

अबकी बार

05 **आपातकाल का सिंहावलोकन**

समान्य रूप से दो प्रश्न सहज भाव से मस्तिष्क में उठते हैं। पहला यह कि क्या आपातकाल आवश्यक था ? दूसरा यह कि क्या जे.पी. आंदोलन से बनी परिस्थितियों या...

संपादकीय 04
विरोध ही आंदोलन बन गया 09
लोक संघर्ष की वाहक बनी अभाविप 11
गुजरात नवनिर्माण आंदोलन : अभाविप ने लिखा नया इतिहास 15
'सतत पर्यावरण' इंटर्नशिप में विद्यार्थियों ने किया वन से जुड़े पहुलओं का अध्ययन 17
Punyashlok Devi Ahilya Bai Holkar : Life, Administration & Contribution for Society 18
छात्रों के लिए बेहतर विकल्प है दूरस्थ शिक्षा माध्यम 20
रानी लक्ष्मीबाई छात्रा व्यक्तित्व विकास शिविर का समापन 22
Agrivision Convention of North–East Bharat Concludes Successfully 23
A Grand Showcase of Innovation and Collaboration 24
अभाविप ने शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन 25
स्नातक छात्र की निर्मम हत्या के विरोध में अभाविप का प्रदर्शन 26
शिक्षा से ही होगा देश का पूर्ण विकास : प्रफुल्ल आकांत 27
कागज–प्लास्टिक मुक्त होगी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक 28
...एक नायक का विदा होना 29

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

यह यशोगाथा है एक छात्र संगठन की, जिसने न केवल अपनी स्थापना के पच्चीस वर्षों की यात्रा में अखिल भारतीय व्याप पाया, अपितु सत्ता की निरंकुशता को चुनौती देने का सत्साहस भी प्रकट किया।

आपातकाल की घटना को पचास वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। लोग इसे स्वतंत्रता का दूसरा आन्दोलन कह कर पुकारते हैं। इस आन्दोलन से उपजा नेतृत्व राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज पर उभरा और खो गया। मुठ्ठी भर लोग ही बचे जो अवसर पाने पर अपने आपको सत्ता और धन के आकर्षण से बचा सके। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़कर सत्ता पाने वाले अधिकांश लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे और काल के प्रवाह में विलीन हो गए।

स्वतंत्र भारत में जब-जब कोई भ्रष्टाचार और अपराध के विरुद्ध खड़ा हुआ, समाज ने उसे सिर-आंखों पर बिठाया है। दुर्भाग्य से ऐसा हर आन्दोलन अपने पीछे कड़वी स्मृतियां छोड़ गया। इस अंधकार में उजाले की किरण के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) और कुछ समविचारी संगठनों ने अपनी साख बनाए रखी। यही कारण है कि अभाविप को समाज का विश्वास प्राप्त हुआ, जिसका प्रमाण कुछ ही दशकों में उसका विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन बन जाना है।

नवनिर्माण आन्दोलन की भूमि पर सम्पन्न होने जा रही इस वर्ष की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में निस्संदेह जहां उस यशस्वी आन्दोलन की स्मृतियां पुनः जीवंत हो उठेंगी, वहीं अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मनाभ आचार्य और पूर्व महामंत्री सुशील मोदी की स्मृति व्यथित भी करेगी।

भारत और भारतीयता के जिस विचार को लेकर अभाविप ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, उसे यथेष्ट प्रतिसाद मिला है। स्वर्ण जयन्ती वर्ष में हमने भारत को विश्वमालिका में यथोचित स्थान दिलाने तथा सशक्त, समृद्ध और स्वाभिमानी भारत गढ़ने का संकल्प लिया था। अमृत महोत्सवी वर्ष में हम भारत को उस दिशा में बढ़ते हुए देख रहे हैं। समाज में जिस प्रकार का सकारात्मक वातावरण निर्माण होने का विश्वास व्यक्त किया गया था, वह आज साक्षात है। इस प्रयत्न में अनेक पीढ़ियों का जीवन खपा है।

इस माह आपातकाल में तानाशाही को चुनौती देने वाले अभाविप कार्यकर्ताओं में से एक प्रमुख व्यक्तित्व सुशील मोदी हमारे बीच नहीं रहे। आपातकाल के बाद वह परिषद के पूर्णकालिक बने तथा तीन वर्ष तक राष्ट्रीय महामंत्री के दायित्व का निर्वहन किया।

बिहार से भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रारंभ हुए छात्र आन्दोलन ने देशव्यापी स्वरूप धारण किया, जिसकी परिणति आपातकाल की समाप्ति तथा सत्ता परिवर्तन के रूप में हुई। इससे ठीक पहले 1973 में गुजरात में भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध आन्दोलन हुआ था। मोरबी से प्रारंभ इस स्वतःस्फूर्त आन्दोलन को संगठनात्मक एवं रणनीतिक आधार अभाविप ने ही दिया। गुजरात में भी आन्दोलन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को सत्ता से बाहर जाना पड़ा।

नवनिर्माण आन्दोलन की भूमि पर सम्पन्न होने जा रही इस वर्ष की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में निस्संदेह जहां उस यशस्वी आन्दोलन की स्मृतियां पुनः जीवंत हो उठेंगी, वहीं अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मनाभ आचार्य और पूर्व महामंत्री सुशील मोदी की स्मृति व्यथित भी करेगी। यह स्मृतियां हमारी धरोहर हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं की स्मृति, हमें निरंतर कर्तव्य-पथ पर चलने की प्रेरणा देती हैं।

सत्रावसान का समय है। सभी विद्यार्थी नए सत्र में अपने भविष्य के सपनों को साकार करने के उपक्रम में संलग्न हैं। सभी को उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाओं सहित

आपका
संपादक

फाइल फोटो

आपातकाल का सिंहावलोकन

समान्य रूप से दो प्रश्न सहज भाव से मस्तिष्क में उठते हैं। पहला यह कि क्या आपातकाल आवश्यक था ? दूसरा यह कि क्या जे.पी. आंदोलन से बनी परिस्थितियों या दबाव के कारण आपातकाल लगाया गया था ?

■ **रामबहादुर राय**

26 जून 2024 को आपातकाल के पचास वर्ष पूरे हो रहे हैं। अगर पीछे मुड़ कर इसे हादसे या दुर्घटना के रूप में देखें तो कुछ लोगों में आपातकाल को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पहला भ्रम तो यही है कि आपातकाल 25 जून 75 को लगा था। जबकि ऐसा नहीं है। आपातकाल की आधिकारिक घोषणा 26 जून की सुबह रेडियो पर आकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वयं की थी। पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रामाणिक आधार कांग्रेस के तत्कालीन नेता एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे की वह गवाही है, जो गवाही उन्होंने शाह आयोग में दी थी। शाह आयोग का गठन आपातकाल में हुई ज्यादतियों की जांच के लिए 1977 में किया गया था।

तत्कालीन समय में सिद्धार्थ शंकर रे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होने के साथ ही बैरिस्टर एवं इंदिरा गांधी के करीबी नेताओं में थे। 12 जून 75 को इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित हुआ तो सिद्धार्थ शंकर रे को दिल्ली बुला लिया गया था। उन्होंने शाह आयोग को बताया था कि 25 जून 75

को सुबह लगभग साढ़े नौ बजे इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि मंत्रिमंडल की बैठक के बिना आपातकाल को कैसे घोषित किया जा सकता है ? कुछ घंटे बाद सिद्धार्थ शंकर ने उन्हें सलाह दी कि अगर राष्ट्रपति आपातकाल सम्बन्धी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो आपातकाल की कार्यवाही शुरू की जा सकती है, परन्तु मंत्रिमंडल की बैठक बुलाए बिना या मंत्रिमंडल की सलाह के बिना आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसके बाद आपातकाल की घोषणा सम्बन्धी दस्तावेज पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बिना तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर कराए गए थे।

आपातकाल की घोषणा सम्बन्धी दस्तावेज का मसौदा 1, अकबर रोड पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुबह चार बजे हुई बैठक में रखा गया। मंत्रिमंडल सचिव ने राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाले आपातकाल के मसौदे को जब पढ़ा तो किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं व्यक्त की, लेकिन विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने यह प्रश्न उठा दिया था कि आखिर आपातकाल की आवश्यकता क्या है? इस तरह देखें तो देश में आपातकाल की घोषणा आधिकारिक रूप से 26 जून की सुबह लगभग आठ बजे रेडियो पर इंदिरा गांधी ने स्वयं की थी, जबकि पुलिस कार्रवाई 25 जून की रात से शुरू हो चुकी थी। समाचार पत्रों के कार्यालयों में छापे डाले जा रहे थे, बिजली काटी जा रही थी और गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी थीं। दिल्ली में गांधी शांति प्रतिष्ठान से जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ़्तारी की सूचना मिलने के बाद चंद्रशेखर जब उनसे मिलने के लिए गए तो उन्हें भी पुलिस ने पकड़ लिया। चंद्रशेखर तत्कालीन समय में कांग्रेस के नेता और कांग्रेस कार्यसमिति के निर्वाचित सदस्य थे। उनका चयन इंदिरा गांधी की इच्छा के विपरीत हुआ था।

यहां पर दो प्रश्न सहज भाव से सभी के मस्तिष्क में उठते हैं। पहला यह कि क्या आपातकाल आवश्यक था और दूसरा यह कि क्या जे.पी. अंदोलन से बनी परिस्थितियों या दबाव के कारण आपातकाल लगाया गया था? दोनों ही प्रश्नों पर विचार करें तो उत्तर 'नहीं' में मिलता है। न तो आपातकाल की आवश्यकता थी और न ही जेपी आंदोलन के कारण आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल सिर्फ इंदिरा गांधी की तानाशाही के कारण लगा था और इसका प्रमाण विशन टंडन की डायरी से मिलता है। वास्तव में आपातकाल लगने का कारण वह मुकदमा था, जिसने इंदिरा गांधी की सत्ता को हिला दिया था। यह मुकदमा 1971 के चुनाव में मिली हार के बाद राजनारायण ने दाखिल किया था, जिस पर तीन वर्ष तक कोई सुनवाई नहीं हुई। नवंबर' 74 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध चुनाव में धांधली करके जीत हासिल करने सम्बन्धी मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा के न्यायालय में शुरू हुई सुनवाई में इंदिरा गांधी को तलब कर लिया गया। इंदिरा गांधी को पांच घंटे तक न्यायालय में

आपातकाल सिर्फ इंदिरा गांधी की तानाशाही के कारण लगा था, जिसका प्रमाण विशन टंडन की डायरी से मिलता है। वास्तव में आपातकाल लगने का कारण वह मुकदमा था, जिसने इंदिरा गांधी की सत्ता को हिला दिया था।

रहना पड़ा और न्यायालय के सामने गवाही देनी पड़ी। प्रधानमंत्री कार्यालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव विशन टंडन ने अपनी डायरी में लिखा है कि ईश्वर न करें, कहीं इंदिरा गांधी मुकदमा हार न जाए, अगर ऐसा हुआ तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए वह दिन-रात एक कर देंगी। विशन टंडन की यह आशंका सच हुई।

12 जून 75 को तीन घटनाएं हुई। सुबह लगभग छह बजे इंदिरा गांधी के नजदीकी राजनयिक डी. पी. धर की मृत्यु हो गई। दिन में इंदिरा गांधी के विरुद्ध न्यायालय का निर्णय आया और शाम को गुजरात विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, जिसमें कांग्रेस चुनाव हार गई और पहली बार जनता मोर्चा चुनाव जीत गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने निर्णय में इंदिरा गांधी

की लोकसभा सदस्यता को रद्द तो कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने ही निर्णय पर स्वतः स्टे भी दिया। इससे उच्चतम न्यायालय में निर्णय की समीक्षा की जा सकती थी। स्टे के कारण उच्चतम न्यायालय का आगामी निर्णय आने तक इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बने रहने में कोई क़ानूनी अड़चन नहीं थी।

12 जून को आए निर्णय के बाद सफदरजंग रोड के पास स्थित तत्कालीन गोल मेथी चौक के पास हरियाणा से चौधरी बंसी लाल के लोग रोजाना आकर इंदिरा गांधी के समर्थन में प्रदर्शन करने लगे थे, तो उधर सिद्धार्थ शंकर रे ने नानी पालकीवाला के साथ मिलकर न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने की तैयारी शुरू कर दी। 20 जून को दो घटनाएं हुई। पहली यह कि इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अवकाशकालीन पीठ के न्यायाधीश वी. आर. कृष्ण अय्यर के समक्ष अपील दाखिल की। दूसरी यह कि इंदिरा गांधी पर कुर्सी छोड़ने के लिए जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस (ओ) और लोकदल ने मिलकर एक मोर्चा बनाया, जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई और नानाजी देशमुख महासचिव बनाए गए। इंदिरा गांधी के विरोध में अब मोर्चा भी सक्रिय हो गया। इधर इंदिरा पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा था, उधर कांग्रेस ने 'इंदिरा इज इंडिया' का नारा लगाना शुरू कर दिया। यह नारा कांग्रेस नेता देवकांत बरुवा ने दिया था, जो तानाशाही सोच को दर्शाता है।

24 जून को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वी. आर. कृष्ण अय्यर ने अपना निर्णय सुनाया। उनके निर्णय को अर्धनारीश्वर स्वरूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इंदिरा को सजा भी मिली और राहत भी दी गई थी। निर्णय में इंदिरा गांधी के लिए राहत यह थी कि वह प्रधानमंत्री बनी रह सकती थी और सजा के रूप में निर्णय से इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल नहीं होती थी क्योंकि उनके चुनाव को वैध करने का कोई आधार ही नहीं था। तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य के अनुसार इंदिरा गांधी को कांग्रेस, संसदीय प्रक्रिया, लोकतंत्र, न्यायपालिका के व्यापक हित में संसदीय पार्टी की बैठक बुलाकर स्वतः प्रधानमंत्री पद को छोड़ देना चाहिए था। अगर वह यह रास्ता अपनाती तो आपातकाल की कोई आवश्यकता नहीं थी।

20 जून को बने जनता मोर्चा ने राजधानी दिल्ली में 25 जून को एक बड़ी रैली की। रैली में जयप्रकाश नारायण को भी हिस्सा लेना था। सरकारी तंत्र ने उस रेलगाड़ी को रद्द कर दिया गया, जिससे जयप्रकाश को आना था। लेकिन वह हवाई जहाज से दिल्ली आए और रामलीला मैदान में अपार जनसमूह के बीच रैली हुई। रैली में जार्ज फर्नांडिस भी मधु लिमये के साथ पहुंचे थे। जार्ज को आशंका हो गई थी और उन्होंने मधु से कहा था कि रात में सतर्क रहना, आपातकाल लगेगा। बाद में जार्ज और मधु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

वैसे देश में आपातकाल थोपने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर प्रधानमंत्री पद की कुर्सी को नहीं छोड़ने के लिए हर तरह के अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करके देश में आंतरिक आपातकाल लगाया गया था। मात्र कुर्सी बचाने के लिए स्वतंत्रता के सभी अधिकारों को बाधित किया गया। आपातकाल के दुष्परिणाम को देखें तो एक अतिरिक्त संवैधानिक सत्ता के रूप में संजय गांधी का उदय हुआ। प्रधानमंत्री के पुत्र के रूप में सत्ता-शासन में उनका अवैध हस्तक्षेप बढ़ता गया और उनके कारनामों ने जनाक्रोश को बढ़ाने में अपना योगदान दिया।

आपातकाल को सत्तर के दशक में गुजरात नवनिर्माण आंदोलन और बिहार आंदोलन से जोड़ कर देखा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। गुजरात नवनिर्माण आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। यह आंदोलन मोरबी में उन विद्यार्थियों ने आरम्भ किया था, जो अपने शिक्षण संस्थान से जुडी विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे थे। यह आंदोलन विद्यार्थियों ने शुरू किया था और फिर इसका प्रसार हुआ। इस अंदोलन के समर्थन में जयप्रकाश नारायण भी जनवरी 74 में गुजरात गए थे। यहां पर दो बातें समझना आवश्यक है। पहला यह कि जो यह समझते हैं कि बिहार का छात्र आंदोलन गुजरात में हुए आंदोलन की आगामी कड़ी थी, तो वह गलत हैं। दूसरा यह कि छात्रों की समस्याओं से

पैदा हुए स्वतः स्फूर्त आंदोलन में आग लगाने का काम इंदिरा गांधी के इशारे पर ख़ुफ़िया एजेंसियों ने किया था। तत्कालीन समय में इंदिरा गांधी चाहती थी कि गुजरात के मुख्यमंत्री घनश्याम लाल ओझा बनें, लेकिन चिमन भाई पटेल ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। इंदिरा गांधी चिमन भाई को पद से हटाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने आंदोलन का प्रयोग अवसर के रूप में किया।

1973 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) का राष्ट्रीय अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। अधिवेशन का उद्घाटन जे. बी. कृपलानी ने किया। अधिवेशन से पहले अभाविप ने बिहार में जो किया, उसे भी समझने की आवश्यकता है। बिहार में 1973 के मध्य में पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव होने थे। अभाविप मंत्री के रूप में मैं स्वयं चुनाव से जुड़ी व्यवस्थाओं को देख रहा था। अभाविप का लक्ष्य चुनाव को जीतना था। इसीलिए समाजवादी युवजन सभा, युवा कांग्रेस सहित कई अन्य छात्र संगठन एक साथ मिलकर कार्य कर रहे थे। तत्कालीन समय में राज्य में काम कर रहे संघ के विभाग प्रचारक के. एन. गोविंदाचार्य ने पैनल के लिए अभाविप कार्यकर्ता सुशील मोदी और रविशंकर प्रसाद का नाम सुझाया। पैनल चुनाव जीत गया। पैनल की जीत बिहार की छात्र राजनीति के लिए एक बड़ी जीत थी क्योंकि पहली बार अभाविप के पैनल ने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। अभाविप कार्यकर्ता सुशील मोदी महासचिव, रविशंकर प्रसाद सह सचिव और लालू प्रसाद अध्यक्ष बने।

अभाविप पैनल की यह जीत बिहार में छात्रसंघ की एक बड़ी जीत के रूप में देखी गई। इसके बाद पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ ने छात्रों से जुडी समस्यायों को दूर करने के उद्देश्य से एक आंदोलन की तैयारी आरम्भ कर दी। इसके लिए अन्य सभी छात्र संगठनों से संपर्क किया गया। नवंबर'73 में अभाविप का तीन दिवसीय अधिवेशन धनबाद में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में तत्कालीन संयुक्त बिहार (वर्तमान बिहार एवं झारखंड) के सभी चालीस जिलों से अभाविप से जुड़े विद्यार्थियों एवं अध्यापकों ने हिस्सा तो लिया ही, साथ ही अन्य सहयोगी छात्र संगठनों के बड़े नेता पर्यवेक्षक के रूप में अधिवेशन में आए, जबकि कुछ वाह्य संगठनों के नेता व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। अभाविप के इसी अधिवेशन से बिहार में छात्र आंदोलन की नींव पड़ी। धनबाद अधिवेशन के बाद पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ ने राज्य के छात्र नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया। अभाविप द्वारा फरवरी' 74 को आयोजित सम्मेलन में सभी छात्र संगठनों के नेताओं एवं प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यह अलग बात है कि बाद में वामपंथी छात्र संगठनों ने इंदिरा गांधी के प्रति अपना समर्थन दिखाते हुए अपनी दूरी बना ली। सम्मेलन के बाद अभाविप सहित अन्य छात्र संगठनों ने ग्यारह सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया, जिसके बाद निर्धारित रणनीति पर मार्च' 74 को बिहार में छात्र आंदोलन आरम्भ हुआ।

1971 में मिली पराजय के कारण तत्कालीन समय में विपक्ष हतप्रभ था। अभाविप द्वारा उठाए जा रहे कदमों से विपक्षी नेताओं में यह उत्सुकता थी कि अभाविप यह सब किसी सनक में तो नहीं कर रही है। विपक्षी नेता लगातार प्रश्न उठा रहे थे कि आगामी छात्र आंदोलन का जो आह्वान किया है, उसमें कितने लोग हिस्सा लेंगे? जब उनको यह बताया जाता था कि संख्या हजारों में होगी, तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता था। जब 18 मार्च' 74 को आंदोलन आरम्भ हुआ तो पटना की सड़कों पर जुटी छात्रों की संख्या को देखकर हर कोई आश्चर्य में था। पुलिस कार्रवाई के कारण उस दिन हिंसा हुई। बाद में जयप्रकाश नारायण भी छात्र आंदोलन से जुड़ गए और 8 अप्रैल को उन्होंने जेपी आंदोलन शुरू कर दिया।

अभाविप छात्र शक्ति का प्रतिनिधि संगठन धीरे-धीरे बना है। उसका जो वैचारिक और संगठनात्मक विकास हुआ है, उसमें बहुतों ने अपनी जिंदगी लगा दी। आज 2024 में अभाविप बड़े छात्र संगठन के रूप में है, जिसे देखकर यह संतोष होता है कि संगठन से हम भी जुड़े हुए थे और हमने भी कुछ किया है। ■

(लेखक अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं। यह आलेख राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम से हुई उनकी बातचीत पर आधारित है।)

विरोध ही आंदोलन बन गया

फाइल फोटो

■ राजकुमार भाटिया

वर्ष 1973 का अंत होने वाला था। महंगाई और भ्रष्टाचार की चुभन पूरे देश में थी। उन्हीं दिनों गुजरात के एक इन्जीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में भोजन शुल्क बढ़ाया गया। विद्यार्थियों ने इस वृद्धि का विरोध किया। कुछ और महाविद्यालयों के छात्रावासों ने भी शुल्क बढ़ाया। वहां भी विरोध होने लगा। विरोध इतना प्रबल होता चला गया कि महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों ने आंदोलन छेड़ दिया, जिसे नवनिर्माण आंदोलन कहा गया।

आंदोलन का प्रारंभ स्वयंस्फूर्त था, परंतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने न केवल उसका समर्थन किया, अपितु बड़ी सीमा तक उसका नेतृत्व भी किया। महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध विद्यार्थियों का यह आंदोलन जनता का आंदोलन बन गया और तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को इसके लिए दोषी माना गया। उनके त्यागपत्र की मांग हुई। आंदोलन इतना प्रभावी था कि मुख्यमंत्री ने पद छोड़ा, विधानसभा चुनाव हुए और नई सरकार बनी।

लेकिन मंहगाई और भ्रष्टाचार की चुभन तो पूरे देश में थी। बिहार अभाविप के नेतृत्व को लगा कि गुजरात जैसा आंदोलन बिहार में भी होना चाहिए। नेतृत्व ने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में प्रमुख पदाधिकारी अपने दो कार्यकर्ताओं-सचिव सुशील मोदी एवं सह-सचिव रविशंकर प्रसाद को निर्देश दिया कि वह छात्र संघ के तत्वावधान में बिहार में आंदोलन की नींव डालें। तत्कालीन समय में लालू प्रसाद यादव छात्र संघ के अध्यक्ष थे। आंदोलन प्रारंभ करने में उन्होंने भी भूमिका निभाई। फरवरी 1974 से छात्रसंघ के नेतृत्व में बिहार

में आंदोलन पनपने लगा। यहां भी कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर को दोषी माना गया और उनके त्यागपत्र की मांग की गई।

यहां यह जानना भी आवश्यक है कि अभाविप ने 1971 से "छात्र आज का नागरिक है" के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उसी के अंतर्गत देश-समाज के व्यापक हित में छात्रों की आंदोलनकारी भूमिका को रेखांकित किया गया। यह कहा जा सकता है कि अभाविप, बिहार के नेतृत्व ने छात्रों की इसी भूमिका को निभाने की पहल की और बिहार आंदोलन जड़ पकड़ने लगा।

जीवन भर आदर्शों पर चलने वाले एवं बड़ी आयु वाले बाबू जयप्रकाश नारायण तत्कालीन समय में

जयप्रकाश जी ने जबसे छात्र आंदोलन का नेतृत्व संभाला, उसके बाद कई घटनाक्रम हुए। आंदोलन देशव्यापी हुआ, छात्रों के साथ-साथ कांग्रेस विरोधी राजनीतिक दल आंदोलन से जुड़ते गए और जयप्रकाश जी ने आंदोलन को महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों तक सीमित नहीं रखा। तत्कालीन समय में देश में अन्य कई ज्वलंत मुद्दे भी जनता के आक्रोश को बढ़ा रहे थे।

राष्ट्रीय राजनीति से विमुख होकर बिहार के एक छोटे से क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे। पहले गुजरात आंदोलन और फिर बिहार आंदोलन को उन्होंने अपना नैतिक समर्थन प्रदान किया था। बिहार आंदोलन का छात्र नेतृत्व इस बारे में स्पष्ट था कि यदि जयप्रकाश जी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे तो आंदोलन अधिक प्रभावी हो जाएगा। इसके बाद छात्र नेतृत्व ने जयप्रकाश जी से आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया। जयप्रकाश जी ने निर्णय करने के लिए समय लिया। साथ ही उन्होंने यह शर्त रखी कि आंदोलन पूर्णतः अहिंसक होगा। छात्र नेतृत्व ने उनकी शर्त को स्वीकार किया और फिर जयप्रकाश जी ने आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। बिहार में कांग्रेसी सरकार सत्ता में थी, इसीलिए कांग्रेस विरोधी राजनीतिक दल भी आंदोलन से जुड़ गए।

फरवरी 1974 से जून 1975 तक की आंदोलन की एक लंबी कहानी है। परंतु उसकी मुख्य विशेषता यह भी रही कि आंदोलन केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 'बिहार' आंदोलन धीरे-धीरे राष्ट्रीय आंदोलन बनता गया क्योंकि महंगाई और भ्रष्टाचार तो देशव्यापी मुद्दे थे। इसीलिए शनैः शनैः जनाक्रोश तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर मुड़ने लगा। 12 जून 1975 की एक घटना से अनपेक्षित तरीके से इंदिरा गांधी कटघरे में खड़ी हो गई।

इंदिरा गांधी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में राजनारायण को पराजित किया था और चुनाव में राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीतने का मुकदमा कर दिया था। इस मुकदमे का निर्णय 12 जून 1975 को आया, जिसमें इंदिरा गांधी पराजित हुई। लगभग एक वर्ष के आंदोलन और मुकदमा हारने के कारण इंदिरा गांधी बहुत दबाव में थी। वह मुकदमा हारी, पर प्रधानमंत्री पद पर बनी रही। 12 जून से 25 जून के बीच इंदिरा गांधी के त्यागपत्र की मांग पूरे देश में बहुत जोरों से उठी, जिसके बाद 26 जून को देश में उन्होंने देश में आपातकाल लागू कर दिया।

जयप्रकाश जी ने जबसे छात्र आंदोलन का नेतृत्व संभाला, उसके बाद कई घटनाक्रम हुए। आंदोलन देशव्यापी हुआ, छात्रों के साथ-साथ कांग्रेस विरोधी राजनीतिक दल आंदोलन में सम्मिलित हुए और जयप्रकाश जी ने आंदोलन को महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों तक सीमित नहीं रखा। तत्कालीन समय में देश में अन्य कई ज्वलंत मुद्दे भी जनता के आक्रोश को बढ़ा रहे थे। जयप्रकाश जी सभी मुद्दों को उठाने लगे, जिनमें शिक्षा व्यवस्था की कमियां और बेरोज़गारी जैसे बड़े मुद्दे थे। इसके बाद जयप्रकाश जी ने समग्र परिवर्तन का नारा देते हुए आंदोलन को सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन का नाम दिया। इससे एक साथ आंदोलन के तीन नामकरण हो गए : बिहार आंदोलन, जयप्रकाश आंदोलन एवं संपूर्ण क्रांति आंदोलन। यदि आपातकाल न लगा होता तो आंदोलन की परिणिति क्या होती? इसका अनुमान लगाना न ही संभव है और न ही आवश्यक। आपातकाल का विरोध ही आंदोलन बन गया। ■

(लेखक अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।)

लोक संघर्ष की वाहक बनी अभाविप

फाइल फोटो

विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की स्थापना के बाद से अब तक की विकास यात्रा के क्रम में सभी प्रकार के संघर्षपूर्ण प्रयासों में 1973 से लेकर 1977 तक का कालखंड ऐतिहासिक कहा जा सकता है। यह समयांतराल भी रहा, जिसमें गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन के माध्यम से अभाविप ने शैक्षिक संस्थानों के भ्रष्टाचार को छात्र आंदोलन का मुद्दा बनाया। 18 मार्च 1974 को पटना विश्वविद्यालय से विधानसभा का घेराव करने जा रहे छात्रों पर पुलिस ने बर्बर अत्याचार करने के साथ ही गोली चलाई। पुलिस की गोली से छह छात्रों की मौत हो गई, सैकड़ों घायल हुए और अनेक छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।

18 मार्च 1974 की घटना की व्यापक प्रभाव पूरे देश पर पड़ा। अभाविप के तत्कालीन नेतृत्वकर्ताओं के प्रयासों से लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। अब यह छात्र आंदोलन पूरे देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नकारात्मक राजनीतिक व्यवहार के साथ ही भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और कुशासन के विरुद्ध देश की जनता में जो आक्रोश पैदा किया, उससे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध एक ऐसा वातावरण बना, जिससे अभाविप का छात्र आंदोलन सत्ता परिवर्तन के आह्वान तक पहुंच गया

और यहीं से आपातकाल की नींव पड़ी।

बिहार में जारी छात्र आंदोलन के बीच अभाविप के तत्कालीन राष्ट्रीय मंत्री राम बहादुर राय एवं अन्य छात्र नेताओं को मीसा कानून में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मीसा अर्थात आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम कानून 1971 में संसद द्वारा पारित वह विवादास्पद कानून था, जिसमें कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्थाओं को बहुत अधिक अधिकार दिए गए थे। आपातकाल के दौरान (1975-1977) कई संशोधन हुए और बहुत से राजनीतिक बन्दियों पर इसे लगाकर जबरन जेल में डाला गया। छात्रों के साथ ही अब आम जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। 12 नवंबर 1974 को उच्चतम न्यायालय ने मीसा कानून के

जनता के रुख से सहमी हुई तानाशाह सत्ता ने 25-26 जून 1975 की मध्यरात्रि में, जब पूरा देश नींद के आगोश में था, लोकतंत्र पर आपातकाल का वज्रपात कर दिया था। 26 जून प्रातः वेला में जब लोगों ने आंखें खोलीं तो सब ओर भयाक्रांत करने वाला वातावरण विद्यमान था। पुलिस व अर्धसैनिक बलों की पदचाप से वातावरण सहम रहा था।

तहत बंद किए गए अभाविप के तत्कालीन राष्ट्रीय मंत्री राम बहादुर राय के साथ अन्य लोगों को मुक्त कर दिया। साथ ही न्यायालय ने अपनी टिप्पणियों में मीसा के अंतर्गत की गई गिरफ्तारियों को अवैध करार दिया।

6 अक्टूबर 1974 को आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में संसद भवन पर सरकारी नीतियों के विरुद्ध हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमें छात्र भी बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने प्रकारांतर से अभाविप के भावी संघर्ष का बिगुल फूंक दिया। 31 अक्टूबर 1974 को लोकनायक जयप्रकाश को सुनने के लिए छात्र हजारों की संख्या में एकत्र हुए। इसी भाषण में लोकनायक ने 'संपूर्ण क्रांति' का आह्वान किया। अभाविप की प्रभावशील सक्रियता के कारण छात्र-आंदोलन का ज्वार अपने चरम पर आ गया और देश के सभी शैक्षिक संस्थानों को अपने प्रभाव में लेने के लिए उद्यत था। इसी बीच अभाविप की योजना से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के तत्वावधान में एक अखिल भारतीय छात्र नेता सम्मेलन किया जाना सुनिश्चित हुआ, जिसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी उपस्थित रहे। संघर्ष को अखिल भारतीय स्वरूप देते हुए कुछ संयुक्त कार्यक्रम भी निर्धारित किए गए।

4 नवंबर, 1974 को 'पटना और दिल्ली बंद', दोनों एक साथ आयोजित हुए। पटना में लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में विशाल छात्र जनसमूह सभी प्रतिबंधों एवं अवरोधों को तोड़ता हुआ सड़कों पर उतर आया। पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया जिसमें जेपी भी घायल हो गए। लोकनायक जयप्रकाश को पुलिस की भीषण मार से बचाते हुए जनसंघ के तत्कालीन संगठन मंत्री नानाजी देशमुख का हाथ टूट गया। उसी दिन दिल्ली बंद भी अभूतपूर्व रूप से सफल रहा। दोनों ही स्थानों पर अभाविप की मुख्य भूमिका रही। 8-10 नवंबर 1974 को अभाविप का रजत जयंती राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में हुआ। इधर मुंबई में अधिवेशन हो रहा था और उधर बिहार में अभाविप कार्यकर्ता जेल के सीखचों में बंद थे।

परिषद के तत्कालीन राष्ट्रीय संगठन मंत्री मदन दास देवी ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, "स्वराज्य के लिए छात्रशक्ति के नेतृत्व में देशव्यापी लोक संघर्ष का आह्वान।" इस शीर्षक का यह प्रस्ताव कई अर्थों में ऐतिहासिक भी है, जिसमें उस समय की त्रासद अवस्था को व्यक्त करते हुए कहा गया कि अभाविप का यह रजत जयंती वर्ष अधिवेशन देश में विद्यमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक दुरावस्था की गंभीरता पर गहरी चिंता प्रकट करता है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के उपरांत नेतृत्व को निरंतर 27 वर्षों तक निरंकुश रूप से शासन के संचालन का अवसर मिला, किंतु वह देश को समृद्ध, स्वावलंबी, शक्तिशाली

और महान नहीं बना सका। प्रस्ताव में आमूल-चूल परिवर्तन हेतु युवा पीढ़ी से आगे आने का आह्वान किया गया। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, कुशिक्षा, विकृत लोकतंत्र एवं अव्यवस्था के विरुद्ध चल रहे संघर्ष को सफल करने के लिए देश की आम जनता व युवा पीढ़ी से 'संपूर्ण क्रांति' के अभियान में सम्मिलित होने का आह्वान भी प्रस्ताव में किया गया। इसी प्रस्ताव में बिहार विधानसभा को भंग करने तथा पिछले आठ माह से मीसा के तहत बंदी परिषद कार्यकर्ताओं, छात्रों व नागरिकों को रिहा करने की पुनः मांग की गई।

मध्यरात्रि में ही प्रमुख विपक्षी नेता, लोक संघर्ष समिति के प्रमुख सदस्य, छात्र संघर्ष समिति के

आपातकाल के विरोध हेतु अभाविप ने देश भर में विभिन्न प्रयोगात्मक तरीके अपनाए, जिनमें से एक प्रयोग था- महात्मा गांधी के चित्र और उनके ही वाक्य 'असत्य, अन्याय और दमन के सामने झुकना कायरता है', जैसे अनेक स्टीकर एवं पोस्टर प्रकाशित एवं प्रसारित करना। पुलिसकर्मी महात्मा गांधी के इन पोस्टरों को जहां भी देखते उन्हें पेट्रोल डाल कर जला देते थे।

नेतागण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं अभाविप के प्रमुख कार्यकर्ता, आलोचक पत्रकार-संपादक एवं कांग्रेस में ही इंदिरा गांधी की कार्य-शैली से मतभेद रखने वाले नेता, सभी गिरफ्तार किए जा चुके थे। नागरिकों की स्वतंत्रता पर तानाशाही के ताले लटक रहे थे। समाचार पत्रों पर प्रेस सेंसरशिप लागू करके आम नागरिकों के संविधान-प्रदत्त मौलिक अधिकार भी निलंबित किए जा चुके थे। यह पूरे देश में हो रहा था। जो भी इंदिरा सरकार के विरोध में थे, वह भी प्रशासन की ताड़ना का शिकार होने लगे।

26 जून को विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय छात्र संघर्ष समिति के संयोजक अरुण जेटली के नेतृत्व में आपातकाल की घोषणा के विरुद्ध पहली आवाज मुखरित हुई। कुलपति कार्यालय के सामने छात्रों के एक समूह को संबोधित करते हुए अरुण जेटली को मीसा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

अब सरकार की वक्रदृष्टि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर थी, जिसकी संगठन-शक्ति से सरकार सर्वाधिक भयभीत थी। संघ को बदनाम करने हेतु सरकार ने निर्लज्जतापूर्वक अपप्रचार का सहारा लिया और 14 जुलाई 1975 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित 25 संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया। संघ प्रमुख बालासाहब देवरस को नागपुर स्टेशन पर 14 जुलाई को ही बंदी बना लिया गया। देश भर के संघ कार्यालयों पर छापे डाल कर सील कर दिया गया।

आपातकाल के विरोध हेतु अभाविप ने देश भर में विभिन्न प्रयोगात्मक तरीके अपनाए, जिनमें से एक प्रयोग था- महात्मा गांधी के चित्र और उनके ही वाक्य 'असत्य, अन्याय और दमन के सामने झुकना कायरता है', जैसे अनेक स्टीकर एवं पोस्टर प्रकाशित एवं प्रसारित करना। पुलिसकर्मी महात्मा गांधी के इन पोस्टरों को जहां भी देखते उन्हें पेट्रोल डाल कर जला देते थे। अभाविप के अनेक कार्यकर्ता इन पोस्टरों को बांटते, चिपकाते हुए गिरफ्तार कर लिए गए, जिन्हें बाद में न्यायालयों ने निर्दोष घोषित कर दिया। आपातकाल के रूप में देश पर थोपी गयी क्रूर तानाशाही के विरुद्ध देशव्यापी जन-आंदोलन में अभाविप की व्यापक भूमिका और छात्रों की सहभागिता बढ़ाने के दायित्व का विचार करने के लिए एक भूमिगत अखिल भारतीय बैठक अहमदाबाद में संपन्न हुई। इसमें परिषद की गतिविधियों को खुले एवं भूमिगत दोनों ही रूपों में संचालित करने का निर्णय लिया गया।

14 नवंबर 1975 से लोक संघर्ष समिति द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह प्रारंभ करने की घोषणा कर दी गई। संपूर्ण देश में बड़ी संख्या में अभाविप के कार्यकर्ताओं ने 'लोक संघर्ष समिति' के सदस्य के रूप में सत्याग्रह में भाग लिया। कुल मिला

कर देश में परिषद के 4,500 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए और मीसा के तहत 650 कार्यकर्ता को जेल में डाला गया। 1,500 कार्यकर्ता डीआईआर कानून में बंद रहे। लगभग ग्यारह हजार छात्रों ने सत्याग्रह किया एवं इतनी ही संख्या में अभाविप कार्यकर्ताओं ने बड़ी सतर्कता, धैर्य एवं अत्यंत साहसपूर्वक भूमिगत कार्यों और गतिविधियों का संचालन किया।

वास्तव में आपातकाल में अभाविप कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न प्रांतों में निर्वाह की गयी अद्वितीय, शौर्यपूर्ण एवं रोचक भूमिका किसी स्वतंत्र पुस्तक का विषय हो सकती है। केरल में जहां छोटे-बड़े अनेक नगरों में आपातकाल के विरोध में प्रदर्शन हुए और 'क्विट इंडिया' की शैली में 'क्विट इंदिरा' का उद्घोष सब ओर गूंजने लगा। केरल में सत्याग्रहियों पर सर्वाधिक पाशविक अत्याचार हुए। केरल में अभाविप का काम कम होने के बावजूद संघ की योजना तथा 'लोक संघर्ष समिति' के सत्याग्रह के प्रचार कार्य में परिषद के छात्र-कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग रहा। 'कुरुक्षेत्र' नामक पत्रक के वितरण का दायित्व अभाविप पर ही था। तमिलनाडु में अप्रैल 1975 में लोकनायक जय प्रकाश के राज्य-प्रवास के दौरान अभाविप कार्यकर्ताओं ने स्थान-स्थान पर बड़ी संख्या में उपस्थित होकर उनके स्वागत- कार्यक्रमों के आयोजन किए।

14 नवंबर 1975 से लोक संघर्ष समिति द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह प्रारंभ करने की घोषणा कर दी गई। संपूर्ण देश में बड़ी संख्या में अभाविप के कार्यकर्ताओं ने 'लोक संघर्ष समिति' के सदस्य के रूप में सत्याग्रह में भाग लिया। कुल मिला कर देश में परिषद के 4,500 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए और मीसा के तहत 650 कार्यकर्ता को जेल में डाला गया।

इसी तरह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर-पूर्व के राज्य, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर सहित शायद ही कोई ऐसा स्थान रहा होगा, जहां अभाविप ने अपना परचम नहीं लहराया होगा। अभाविप पर केंद्रित पुस्तक ध्येय-यात्रा के प्रथम खंड में आपातकाल के दौरान विभिन्न राज्यों में अभाविप कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों की विस्तार में की गई चर्चा अभाविप की सक्षम-समर्थ संगठन शक्ति को सामने रखती है।

21 माह की अवधि के बाद 21 मार्च 1977 को आपातकाल के राक्षस का वध तो हो गया लेकिन आपातकाल में जो भी अत्याचार हुए, उन्हें इतिहास में सदैव लोकतंत्र पर काले धब्बे के रूप में देखा जाएगा। ■

(पुस्तक ध्येय यात्रा के सम्पादित अंश)

प्रिय मित्रों !

शिक्षा - क्षेत्र की प्रतिनिधि - पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' जून 2024 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई - मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

गुजरात नवनिर्माण आंदोलन
अभाविप ने लिखा नया इतिहास

दिसंबर'1973 में गुजरात के मोरबी नगर में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रावास शुल्क, भोजन शुल्क एवं अध्ययन शुल्क में की गई अप्रत्याशित वृद्धि के विरुद्ध सर्वप्रथम छात्र आंदोलन प्रारंभ हुआ। कुछ समय पश्चात राजकोट नगर में पानी की भयंकर समस्या को लेकर वहां भी छात्र सड़कों पर उतर आए। इसी बीच दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई भारी वृद्धि ने वरिष्ठ नागरिकों को एक जन-आंदोलन करने के लिए बाध्य कर दिया दिया।

जून 1973 में भोपाल में हुई राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में शैक्षिक संस्थानों के भ्रष्टाचार को छात्र आंदोलन का मुद्दा बनाने के निर्णयानुसार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद(अभाविप) राज्य में विभिन्न प्रश्नों को लेकर आंदोलन चला चुकी थी, जिससे पूरे राज्य में अभाविप ने छात्रों को संगठित करके सुनियोजित छात्र आंदोलन एवं उसमें छात्रों की सामूहिक सहभागिता कराने के लिए आवश्यक क्षमता एवं तंत्र विकसित कर लिया था। इसीलिए जब मोरबी तथा राजकोट के छात्र अपनी समस्याओं के समाधान हेतु आंदोलनरत हुए तो स्वाभाविक रूप से अभाविप कार्यकर्ता भी उनसे जुड़ गए और आंदोलन को दिशा देना आरंभ कर दिया। इसी समय नवनिर्माण युवक समिति एवं नवनिर्माण युवती समिति का गठन किया गया।

अहमदाबाद स्थित अभाविप कार्यालय ही इन समितियों की गतिविधियों का केंद्र बना। अभाविप कार्यकर्ता मनीष जानी को युवक समिति का संयोजक और सोनल देसाई को युवती समिति की संयोजक बनाया गया। यह कहा जा सकता है कि गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन स्वतः आरंभ हुआ था, किंतु उसे व्यवस्थित आकार देने का कार्य अभाविप ने किया। इसका नेतृत्व भी सहज ही अभाविप के हाथों में आ गया। अभाविप के तत्कालीन प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश मंत्री, पूर्व प्रदेश मंत्री इत्यादि अनुभवी कार्यकर्ता नवनिर्माण आंदोलन के कर्णधार बने। अभाविप के तत्कालीन एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन एवं संरक्षण में नवनिर्माण युवक समिति ने आंदोलन को नई दिशा, नए तेवर एवं नवीन उत्साह प्रदान किया।

आंदोलन के आरंभ में छात्र-छात्राएं मात्र शिक्षा मंत्री के त्यागपत्र की मांग कर रहे थे, लेकिन जैसे-जैसे आंदोलन ने जोर पकड़ा, उसमें नए-नए मुद्दे जुड़ते चले गए। पुलिस के दमन चक्र ने भी आंदोलन को व्यापक होने का अवसर दिया और 1973 के अंत तक यह आंदोलन गुजरात के आम नागरिकों और समूचे विपक्ष का आंदोलन बन गया। लेकिन अब शिक्षा मंत्री के साथ

फाइल फोटो

मुख्यमंत्री के त्याग-पत्र की भी मांग उठने लगी। शांतिप्रिय आंदोलन में शामिल युवकों पर लाठीचार्ज और गोलीबारी के कारण हुई मौतों ने आंदोलन को और अधिक दृढ़ता प्रदान की। अब इस्तीफे के साथ ही विधानसभा भंग करने की मांग ने जोर पकड़ लिया।

गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमन भाई ने

शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए न केवल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, बल्कि सेना का भी सहारा लिया, किंतु छात्र अडिग रहे। आंदोलन के नेतृत्व करने वालों को अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए जाने के बावजूद हर कोई आंदोलन को और अधिक तीव्र एवं व्यापक बनाने के लिए सफलतापूर्वक जुटा रहा और 1974 आते-आते यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। सारे देश की दृष्टि गुजरात की तरफ थी। सत्तामद में अंधी तानाशाही एवं छात्रशक्ति के बीच संघर्ष चल रहा था। भ्रष्ट एवं निरंकुश सत्ताधीशों ने अभाविप को इस आंदोलन से अलग करने हेतु साम, दाम, दंड, भेद की नीति अपनाई, किंतु उनके प्रलोभनों को कार्यकर्ताओं ने सहज ढंग से ठुकरा दिया। यह एक ऐसा आंदोलन था, जिसमें गुजरात के सभी स्कूल- कालेज के छात्र अपनी शिक्षा को छोड़ कर सड़क पर उतर कर आंदोलन करते दिखते थे। शिक्षण कार्य ठप हो चुका था। 'झांसी की रानी','टोपी जुलूस', 'सरकार का मृत्यु घर', 'अंधकार व प्रकाश' जैसे नए एवं प्रयोगात्मक कार्यक्रमों के द्वारा यह आंदोलन जन-जन तक पहुंच गया। चूल्हा बंद, महिला फरियाद केंद्र, प्रपंचवती मां का कोर्ट जैसे अन्य अनगिनत कार्यक्रमों द्वारा विद्यार्थियों ने इस आंदोलन में चेतना भर दी।

15 मार्च, 1974 को अभाविप के नेतृत्व में बीस हजार से भी अधिक संख्या में अनुशासित विद्यार्थियों का एक समूह अहमदाबाद राजभवन पहुंच गया। अभाविप के तत्कालीन प्रदेश संगठन मंत्री अरुण भाई ओझा तथा कुछ अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर गुजरात उच्च न्यायालय एवं नागरिक न्यायालय में बार एसोसिएशन ने एक दिन के लिए हड़ताल की और पूरे राज्य में विरोध प्रकट करते हुए विद्यार्थियों ने उपवास भी शुरू कर दिए। मीडिया ने अभाविप के इस आंदोलन की मुक्तकंठ से प्रशंसा की और प्रांत मंत्री की गिरफ्तारी पर गुजरात में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले दैनिक संदेश ने 16 मार्च 1974 को लिखा- "विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री अरुण ओझा की आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तारी हुई है। वास्तव में विद्यार्थी आंदोलन की अवधि में शांतिमय तरीके से शालीनतापूर्वक, व्यवस्थित सविनय कानून भंग की और विद्यार्थी भाई-बहनों को ले जाने का कार्य उन्हीं नवनिर्माण समितियों ने किया है, जिन पर विद्यार्थी परिषद की पकड़ थी। इसी दिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा-"अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नियंत्रण में रहा नवनिर्माण समिति का पालड़ी केंद्र खुद के विभिन्न कार्यक्रमों के कारण अग्रगामी केंद्र बन गया।"

विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन से लाभ उठाने के प्रयास किए, किंतु सभी असफल रहे। प्रारंभ में कांग्रेस के नेताओं ने मार्गदर्शन एवं आर्थिक सहायता द्वारा नवनिर्माण समिति पर वर्चस्व स्थापित करने के यत्न किए। उन्होंने गुजरात के सामाजिक कार्यकर्ता रविशंकर महाराज और जयप्रकाश नारायण का भी अपने लाभ हेतु उपयोग करने का प्रयास किया। कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता मोरारजी देसाई ने आमरण उपवास प्रारंभ करके गुजरात विधानसभा विसर्जन का यश लेने का प्रयत्न किया, किंतु सत्य सभी जानते हैं कि विजय समिति की हुई है। इधर इंदिरा कांग्रेस की सत्ता गुजरात से उखड़ रही थी, उधर कांग्रेस नवनिर्माण आंदोलन में फूट डालने का कुत्सित प्रयास कर रही थी। जिसके तहत कांग्रेस के तत्कालीन मंत्री चंद्रजीत यादव विशेष रूप से अहमदाबाद आए, किंतु वह युवक समिति को आंदोलन समिति से अलग करने के कुत्सित प्रयास में पूरी तरह असफल हुए। आंदोलन से प्रभावित संपूर्ण समाज का राजनीतिज्ञों पर इतना प्रचंड दबाव बना कि विपक्षी विधायकों का अनुसरण करते हुए सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी विधानसभा से त्याग-पत्र देने आरंभ कर दिए। इस समय गुजरात पुलिस छात्रों पर अमानुषिक अत्याचार कर रही थी।

गुजरात में 73 दिन तक चले इस आंदोलन में 82 लोगों की मृत्यु हुई, 108 घायल हुए और 6,155 लोग गिरफ्तार किए गए। इन अत्याचारों ने जन-सामान्य में एक विस्फोटक आक्रोश भर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उभरे जन-आंदोलन को देखते हुए इंदिरा गांधी ने मुख्यमंत्री चिमन भाई को त्याग-पत्र देने का निर्देश दिया। 7 फरवरी 1974 को मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल ने त्याग-पत्र दे दिया और 15 मार्च 1974 को विधानसभा भंग कर दी गई। गुजरात का यह नवनिर्माण आंदोलन अभाविप के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के छात्र-आंदोलन में अनन्य स्थान रखता है। इसकी सफलता ने छात्र-आंदोलन के विचार को और अधिक सबल बनाया। ■

(पुस्तक ध्येय यात्रा के संपादित अंश)

'सतत पर्यावरण' इंटर्नशिप में विद्यार्थियों ने किया वन से जुड़े पहुलओं का अध्ययन

विकासार्थ विद्यार्थी (एसएफडी) जयपुर प्रांत और टाइगर वॉच संस्था द्वारा सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में पांच दिवसीय 'सतत पर्यावरण' इंटर्नशिप का आयोजन किया गया। इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थियों ने वन एवं वन्यजीवों से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझा। साथ ही राष्ट्रीय उद्यान के निकट वन में जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों के यहां रात्रि विश्राम करके उनकी जीवनचर्या एवं उससे जुडी समस्याओं को जाना।

जल, जंगल, जमीन और जानवर से जुड़े हुए विषयों पर विद्यार्थियों के मध्य जागरूकता और समझ विकसित करने के लिए विकासार्थ विद्यार्थी देशभर में इस तरह के अध्ययन शिविरों का आयोजन करता है। एसएफडी के राष्ट्रीय संयोजक मयूर जव्हेरी ने बताया कि पांच दिवसीय अध्ययन इंटर्नशिप के दौरान प्रमुख रूप से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में मानव और वन जीवन के बीच के संबंधों के साथ ही विकास की संकल्पना, एसएफडी की कार्यपद्धति पर आधारित सत्रों के साथ वन भ्रमण का आयोजन किया गया। इंटर्नशिप में गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बारह विद्यार्थियों ने भाग लिया।

इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय उद्यान से निर्वासित हुए परिवारों के यहां रात्रि विश्राम किया तथा उनके जीवनचर्या को जानकर आने वाली समस्याओं को समझा। एक सत्र भारत में मिलने वाली सांपों की सामान्य प्रजाति, जहरीले

फाइल फोटो

सांपों की पहचान और उनके संरक्षण के संदर्भ में आयोजित किया गया। पूर्व में शिकार करने वाली जनजातियों से मिलना, शिकार छोड़ने के बाद उनके कल्याण के लिए चलाए जाने वाले प्रकल्पों को देखना, वन अधिकारियों से मिलकर वन के विषय में अधिक जानकारी जुटाना भी इंटर्नशिप का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। इस दौरान सवाई माधोपुर स्थित प्राचीन बावड़ी झूमर बावड़ी के संरक्षण के लिए श्रमदान के साथ ही रणथंभौर के किले को देखने और उसके इतिहास की जानकारी भी विद्यार्थियों ने ग्रहण की। वन भ्रमण के समय रणथंभौर की लोकप्रिय बाघिन रिद्धि और इसके तीन शावकों को विद्यार्थियों ने देखा तथा पार्क के अंदर जल संरक्षण की पद्धतियां, जैविक चक्र, खाद्य चक्र आदि विषयों का भी अध्ययन किया। अध्ययन के दौरान पर्यावरणविद धर्मेंद्र खांडल तथा विकासार्थ विद्यार्थी के अखिल भारतीय प्रमुख राहुल गौड़ भी उपस्थित रहे। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

काम्या ने बनाया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड

विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराने वाली काम्या कार्तिकेयन सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं। उन्होंने यह उपलब्धि सोलह वर्ष की आयु में हासिल की है। काम्या अपने पिता एवं भारतीय नौसेना के कमांडर एस. कार्तिकेयन के साथ गत 20 मई को एवरेस्ट की 8,849 मीटर ऊंची चोटी पर पहुंचने में सफल हुई। मुंबई के नौसेना बाल विद्यालय में बारहवीं कक्षा की छात्रा काम्या को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। काम्या ने नेपाल की ओर से सबसे ऊंची चोटी के शिखर तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है। उन्होंने दोपहर 12:35 बजे एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा लहराया। वह 16 वर्ष की आयु में ऐसा करने वाली पहली भारतीय और विश्व की दूसरी सबसे युवा लड़की बन गई हैं। इस सफलता को लेकर भारतीय नौसेना ने उन्हें बधाई दी है। विश्व के सातों पर्वत शिखर पर पहुंचने वाली सबसे युवा लड़की का रिकॉर्ड बनाने के लिए काम्य दिसंबर में अंटार्कटिका में माउंट विंसन मैसिफ की चढ़ाई करेंगी। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

PUNYASHLOK DEVI AHILYA BAI HOLKAR
LIFE, ADMINISTRATION & CONTRIBUTION FOR SOCIETY

■ Dr. Punit Kumar Dwivedi

Punyashlok Devi Ahilya Bai Holkar was a remarkable figure in Indian history, known for her exceptional leadership and compassion towards her people. She ruled the Malwa region of Central Bharat from 1767 to 1795 and is remembered for her progressive administration, social reforms, and devotion to her subjects.

Punyashlok Devi Ahilya Bai Holkar was born in 1725 in the village of Chondi, in the present-day state of Maharashtra. She was married to Khanderao Holkar, the ruler of the Holkar dynasty, at a young age and became queen after his untimely death in battle. As queen, Ahilya Bai took on the responsibility of governing the kingdom and quickly established herself as a wise and just ruler. One of Ahilya Bai's most significant contributions to society was her emphasis on social and economic development. Under her reign, infrastructure projects such as the construction of roads, bridges, and irrigation systems were undertaken to improve the lives of her people. She also promoted trade and commerce, creating a prosperous economy in the region. Ahilya Bai was known for her compassion towards her subjects and was deeply committed to their well-being. She provided support and assistance to the poor and marginalised communities, including widows and orphans, and took measures to ensure their welfare.

Ahilya Bai was also a devout Hindu and patronised religious institutions, building

फाइल फोटो

temples and supporting pilgrimage sites across her kingdom. In addition to her social initiatives, Ahilya Bai was a skilled administrator who implemented efficient governance practices. She appointed capable ministers and administrators, established a system of justice based on fairness and impartiality, and maintained law and order throughout her kingdom. Ahilya Bai was known for her accessibility to her people, who could approach her directly with their grievances and concerns. One of the most enduring legacies of

Ahilya Bai's rule was her commitment to upholding the principles of dharma or righteousness. She was a pious and devout ruler who followed the teachings of Hinduism and sought to govern in accordance with its values.

Devi Ahilya Bai Holkar upheld the rights of her subjects and ensured that justice was served to all, regardless of their social status or background. Devi Ahilya Bai's reign came to an end in 1795, with her death at the age of 70. She was succeeded by her grandson, who continued her legacy of good governance and social reform. Today, Devi Ahilya Bai is remembered as a shining example of a compassionate and competent ruler, whose dedication to the welfare of her people left a lasting impact on Indian history.

Mata Ahilya Bai Holkar was able to maintain stability in her kingdom through her strong leadership, effective governance, and commitment to the welfare of her subjects. She implemented various reforms, improved infrastructure, and promoted education and culture in her kingdom, which helped in strengthening her rule and maintaining peace and prosperity.

Prosperity for people-Steps Taken : Devi Ahilya Bai Holkar implemented several measures to tackle economic challenges and ensure prosperity for her people during her reign. Some of the ways she handled economic challenges include:

Infrastructure development : Devi Ahilya Bai Holkar focused on improving infrastructure in her kingdom by building roads, bridges, and irrigation systems. These developments helped boost trade and agriculture, leading to economic growth.

Support for agriculture : She introduced various agricultural reforms such as providing financial assistance, improved irrigation systems, and promoting new farming techniques to enhance agricultural productivity. This led to increased food production and better livelihoods for her subjects.

Trade and commerce : Devi Ahilya Bai Holkar promoted trade and commerce by establishing trade routes, markets, and encouraging business activities in her kingdom. She also provided security for traders and merchants, which helped in boosting economic activities.

Tax reforms : She implemented fair tax policies and reduced the burden of taxes on common people. This helped in improving the financial condition of the people and encouraged economic growth.

Patronage of arts and culture : Punyashlok Devi Ahilya Bai Holkar provided patronage to artists, craftsmen, and scholars, which helped in the growth of arts and culture in her kingdom. This, in turn, promoted tourism and boosted the economy. Devi Ahilya Bai Holkar's administration focused on holistic development, infrastructure, agriculture, trade, taxation, and cultural growth, which contributed to the prosperity of her people and the economic development of her kingdom.

In conclusion, Punya Shloka Mata Ahilya Bai Holkar was a remarkable leader who ruled with wisdom, compassion, and integrity. Her administration was marked by social reform, economic development, and justice, and her devotion to her people earned her widespread admiration and respect. Ahilya Bai's legacy continues to inspire generations of Indians, who look to her as a role model for good governance and service to society. Her life and work serve as a testament to the power of leadership to bring about positive change and make a lasting impact on the lives of others. ■

(The Author is State Head of Savishkar Malwa)

छात्रों के लिए बेहतर विकल्प है दूरस्थ शिक्षा माध्यम

■ अजीत कुमार सिंह

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय सहित देश के विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों में स्नातक और परा-स्नातक स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में देश के हजारों छात्र ऐसे भी हैं जो केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीयूसीईटी) में असफल होने के साथ ही अन्य विभिन्न कारणों से प्रवेश लेने से चूक गए हैं। उनके सामने समस्या यह है कि वह अपनी शिक्षा को कैसे जारी रखें ?

ऐसे छात्रों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए दूरस्थ या मुक्त शिक्षा माध्यम के द्वार खुले हुए हैं। दूरस्थ शिक्षा माध्यम से वह न केवल उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, बल्कि उच्च शिक्षा ग्रहण करके वह अपने भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिक्षा में केवल परंपरागत पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि आधुनिक समय के अनुरूप साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमता, काल गणना जैसे अनेक पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए हैं। दूरस्थ शिक्षा के द्वार उन सभी विद्यार्थियों के लिए हमेशा खुले रहते हैं, जो नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं।

देश में शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान कर रहे अधिकांश दूरस्थ शिक्षा माध्यम या मुक्त विश्वविद्यालयों में प्रतिवर्ष दो बार प्रवेश एवं परीक्षा का आयोजन किया जाता है। दूरस्थ शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जो पत्राचार या ऑनलाइन मोड पर आधारित होती है। शिक्षा के इस माध्यम में अन्य शिक्षण संस्थानों की तरह छात्रों को नियमित उपस्थिति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होती। दूरस्थ शिक्षा पद्धति में विद्यार्थियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश एवं शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े नियम काफी लचीले होते हैं। मूल रूप से यह शिक्षा पद्धति का वह माध्यम हैं, जहां छात्रों को सप्ताह के अंत में कक्षा, इंटरनेट, वीडियो, कॉन्फ्रेंसिग आदि माध्यमों से शिक्षा दी जाती है।

प्रवेश लेने के लिए नहीं है कोई बाध्यता

दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाले मुक्त विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए सामान्यतः सीयूईटी अंक या मेधा सूची जैसी बाधाएं नहीं होती हैं और प्रवेश लेने के लिए छात्रों को पर्याप्त समय मिलता है। विलम्ब शुल्क के साथ अधिकतर विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया अक्तूबर-नवम्बर तक जारी रहती है। विज्ञान के अतिरिक्त मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) और शिक्षा-स्नातक (बीएड) जैसे कई व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश जांच परीक्षा के माध्यम से होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल आफ ओपेन लर्निंग जहां सितम्बर तक प्रवेश लेने का अवसर देती है, वहीं इग्नू, नालंदा खुला विश्वविद्यालय और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय सहित कई संस्थान वर्ष में दो बार प्रवेश प्रक्रिया संचालित करते हैं। इन संस्थानों में प्रायः पहला सत्र जुलाई में और दूसरा सत्र जनवरी में प्रारंभ होता है। अपनी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार छात्र इन संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं।

सभी विषयों की उपलब्धता

दूरस्थ शिक्षा माध्यम द्वारा विद्यार्थी स्नातक, परास्नातक, पीएचडी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट आदि कोर्स कर सकते हैं। यह छात्रों के लिए बीए, बीकॉम जैसी स्नातक शिक्षा का कारगर माध्यम है। कला और समाज विज्ञान में ऑनर्स कोर्स करने के विकल्प भी दूरस्थ शिक्षा में उपलब्ध हैं। **इग्नू** में कला और वाणिज्य के अलावा साइंस और मैनेजमेंट के पाठ्यक्रमों की शिक्षा दी जा रही है। स्नातक जनरल कोर्स के साथ ही बीएससी जनरल की शिक्षा दी जाती है। छात्र गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं प्राणि विज्ञान जैसे विषय की शिक्षा ले सकते हैं। बैचलर

दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय		
क्रमांक	**विश्वविद्यालय का नाम**	**वेबसाइट**
1	इग्नू	https://ignouadmission.samarth.edu.in/
2	बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय	https://brabu.ac. In/
3	दिल्ली विश्वविद्यालय	https://www.du.ac. In/
4	जामिया मिलिया इस्लामिया	https://jm I.ac. In/
5	सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय	https://smu.edu. In/smu.html
6	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय	https://mdu.ac. In/
7	नालंदा खुला विश्वविद्यालय	https://www.nou.ac. In/adm Iss Ion.html
8	गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय	https://www.gjust.ac. In/
10	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	https://kuk.ac. In/
11	कुवेम्पु विश्वविद्यालय	http://www.kuvempu.ac. In/kan/ Index.php
12	मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय	https://mpbou.edu. In/
13	चंडीगढ़ विश्वविद्यालय	https://www.cuchd. In/
14	केरल विश्वविद्यालय	https://www.cukerala.ac. In/Home
15	उत्तरप्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय	http://www.uprtou.ac. In/
16	उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय	https://www.uou.ac. In/
17	झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय	https://jsou.ac. In/
18	एनआईओएस	https://n Ios.ac. In/h Ind I.aspx

ऑफ साइंस (एनथ्रोपोलोजी), बैचलर आफ टूरिज्म स्टडीज, बैचलर आफ सोशल वर्क, बैचलर आफ कंप्यूटर एप्लिकेशन और मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म जैसे कई कोर्स यहां हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग के रूप में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स के पाठ्यक्रमों की शिक्षा के लिए भी छात्र प्रवेश ले सकते हैं। अब दूरस्थ शिक्षा में बीएड और डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी डीएड कोर्स को भी शामिल कर लिया गया। इसके साथ ही अनुवाद में डिप्लोमा, डिग्री, बी-एलआईएस और एम-एलआईएस कोर्स के साथ ही परास्नातक स्तर पर जेंडर स्टडीज, अनुवाद, समाजशास्त्र, पर्यावरण, सस्टेनेबल एनर्जी, फॉक कल्चर, इनफॉरमेशन सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, अरबी, स्पेनिश, फ्रेंच और शिक्षा में परास्नातक जैसे कोर्स भी छात्रों के लिए आकर्षण का विषय हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत बीए, बीकॉम के साथ ही बीकॉम ऑनर्स का पाठ्यक्रम भी है। यहां अंग्रेजी और राजनीतिशास्त्र ऑनर्स की भी शिक्षा दी जाती है। स्नातक में कई वोकेशनल विषय भी पढ़ाए जाते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पत्राचार माध्यम के रूप में आर्ट्स और कॉमर्स के अलावा बैचलर इन इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन पावर

जेनरेशन, जियोइंफॉर्मेटिक्स और गाइडेंस एंड काउंसिलिंग का कोर्स है।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने भी डिस्टेंस लर्निंग में कई पाठ्यक्रम चलाए हैं। इनमें जनरल आर्ट्स और कॉमर्स के साथ ही गणित और भूगोल में एमएससी और एमए पाठ्यक्रम शामिल हैं। छात्रों के मध्य बैचलर इन इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट और एलएलएम जैसे कोर्स लोकप्रिय हैं। एमसीए, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस और एमबीए इन हॉस्पिटेलिटी मैनजमेंट जैसे कोर्स भी यहां पर हैं।

वर्धा स्थित **महात्मा गांधी हिन्दी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय** देशभर में छात्रों के लिए बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कोर्स उपलब्ध हैं। बी-लिब, एम-लिब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन एवं फिल्म प्रोडक्शन में डिप्लोमा कोर्स यहां से किया जा सकता है। हरियाणा के हिसार स्थित **गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय** द्वारा एमए-मासकॉम एमसीए, एमबीए, एमएससी, एमकॉम, बीए, बी.कॉम जैसे पाठ्यक्रम छात्रों के लिए चलाए जा रहे हैं। स्नातक-परास्नातक कोर्स के अलावा फूड क्वालिटी, फिल्म प्रोडक्शन, ठोस कचरा प्रबंधन इत्यादि में डिप्लोमा कोर्स भी छात्र यहां से कर सकते हैं। इनके अलावा देश में हिमाचल विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) रोहतक, पंजाब टेक्निकल विश्वविद्यालय, अन्नामलाई और पांडिचेरी जैसे कई विश्वविद्यालय भी अपने यहां छात्रों को विभिन्न विषयों में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। ■

। उत्तर प्रदेश ।

रानी लक्ष्मीबाई छात्रा व्यक्तित्व विकास शिविर का समापन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) मेरठ महानगर द्वारा सात-दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई "छात्रा व्यक्तित्व विकास शिविर" का समापन समारोह डी. एन. इंटर कालेज में संपन्न हुआ। शिविर में तीन सौ से अधिक छात्राओं ने हिस्सा लिया। समापन समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री शिवांगी खारवाल ने सभी छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि छात्रा व्यक्तित्व विकास शिविर व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक का सफर तय करेगा। यह शिविर छात्राओं को उनकी पूरी क्षमता को सामने लाने के लिए, उनकी सीमाओं को दूर करने और विश्व की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से लगाए जाते हैं। वर्तमान समय में छात्रों को केवल शैक्षिक रूप से ही उत्कृष्ट बनने के लिए नहीं, बल्कि संवाद, नेतृत्व और मौलिक सोच जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशलों को पोषित करना अति महत्वपूर्ण है। यह कौशल आज की प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में सफलता के लिए अत्यावश्यक है और इसे केवल एक व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम के माध्यम से ही विकसित किया जा सकता है।

फाइल फोटो

समापन समारोह की मुख्य अतिथि डा. नीलम ने कहा कि हम सबको हमेशा नारी के सम्मान हेतु कार्य करना चाहिए। मुख्य वक्ता डा. जूही अग्रवाल ने अभाविप के विषय में विस्तार से जानकारी दी। महानगर अध्यक्ष डा. धर्मेंद्र अहलावत ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में छात्राओं ने शिविर के दौरान सीखे गए आत्मरक्षा तकनीक का भी प्रदर्शन किया। छात्राओं को उनकी प्रतिभा एवं कौशल हेतु प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रांत संगठन मंत्री तरुण सिंह, विभाग संगठन मंत्री अनुज ठाकुर, महानगर मंत्री अभिषेक गोयल सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

AGRIVISION CONVENTION OF NORTH-EAST BHARAT CONCLUDES SUCCESSFULLY

Agrivision 1st Zonal Convention of North-East Bharat, held on May 17th and 18th 2024, at the College of Post Graduate Studies in Agricultural Sciences, Umiam, that was concluded with resounding success. Organized in collaboration with Vidyathi Nidhi, CAU-Imphal, ICAR-NEH and Assam Agriculture University (AAU) Jorhat, the event witnessed participation from over 600 delegates, including esteemed professors, directors, joint directors, deans and students from across India terming the programme an excellent one by the active participation of all participants.

The convention's theme, "Futuristic Agriculture for Atmanirbhar Bharat in the Eastern Himalayan Region," set the stage for two days of insightful discussions and presentations aimed at fostering innovation and self-reliance in the agricultural sector of North-East India. The inaugural session, chaired by Dr. Anupam Mishra, Vice Chancellor of CAU-Imphal, Dr. S.K. Singh, DDG-Horticulture of ICAR, New Delhi, as the chief guest. Guest of Honour Dr. Bidyut C. Deka, Vice Chancellor of AAU, Jorhat, Assam and other notable guests including Govind Nayak, National Joint Organising Secretary of ABVP and Mr. Subham Singh Patel, National Convener of AGRIVISION, graced the event with their presence and that was very charming for all and quite encouraging too. In the vivid presence of all the dignitaries and with their inspiring words, the congregation was very charming and graceful indeed.

Dr. P. K. Pandey, Organizing Secretary of AGRIVISION-2024, welcomed the participants and outlined the aims and objectives of the conclave. Dr. S.K. Singh congratulated the AGRIVISION team and emphasized the vast potential of diverse agro-products, encouraging students to become job providers rather than job seekers. Dr. Anupam Mishra highlighted the importance of creating demand for specialized products and revisiting traditional agricultural wisdom to address contemporary challenges. Dr. Bidyut C. Deka discussed the need for tailor-made

फाइल फोटो

technologies for North-East India's agricultural sector to achieve self-reliance, advocating for the promotion of electronic marketing products and the development of agro-entrepreneurs. Govind Nayak emphasized the role of students as current citizens with the potential to drive national progress and shared various activities undertaken by ABVP at the national level.

The two-day convention included four significant technical sessions during which 103 research papers on various aspects of futuristic agriculture were presented very categorically by the individuals, providing a platform for young researchers to share their findings and innovations, contributing to the advancement of the agricultural sector. Awards were conferred upon the winners of the oral and poster presentations, recognizing the exceptional contributions of young researchers. Every single presentation reflected the deep concentration and dedication of each participant who took part in presentation.

The valedictory session featured State Animal Husbandry and Veterinary Minister, Alexander Laloo Hek, as the chief guest. In his address, Hek underscored the importance of key crops and their export potential, stressing the need for demand-driven research in agriculture. Guest of Honour, Kamalnayan, Zonal Organizing Secretary of ABVP, spoke about the pivotal role of AGRIVISION events in fostering leadership among students, encouraging them to pursue research that benefits farmers in the North-Eastern region. ■

(Rashtriya Chhatrashakti Team)

A GRAND SHOWCASE OF INNOVATION AND COLLABORATION

The "Srishti 2024" event, a remarkable convergence of innovation and collaboration, concluded successfully on May 26th, celebrating three days of technological advancements and educational excellence. Organized by ABVP in collaboration with Yuvaka Sangha, AICTE, VTU, and Atria Institute of Technology, the event witnessed enthusiastic participation from multiple colleges, showcasing a vibrant array of student projects.

Valedictory program on May 26th featured ISRO Chairman S. Somanath as the chief guest. In his address, Somanath discussed the transformative impact of AI, referring to it as "alien intelligence," capable of comprehending human actions but devoid of conscience. He emphasized the potential of virtual reality (VR) in education, the revolutionary effects of 3D manufacturing, and the pivotal roles of AI and robotics in industry automation. Somanath encouraged startups to focus on climate change and drones, stressing the importance of interdisciplinary learning and project-based experiences.

AICTE Chairman Prof. T. G. Sitharam expressed gratitude and highlighted the critical role of innovation in enhancing livelihoods. He noted India's impressive growth, with 25,000 startups, including 125 unicorns, marking the nation's emergence as a global innovation hub.

Prof. Ganeshan Kannabiran, Director of NAAC, emphasized hands-on learning, congratulating participants and stressing the significance of emerging technologies for student projects and career growth. Dr. T. N. Sreenivasa, Registrar (Evaluation) at VTU, praised the participants' dedication and highlighted Srishti's growth with 293 projects. He underscored the importance of patents in motivating student innovation.

S. Balakrishna, National Joint Organising Secretary of ABVP, emphasized harnessing youth power for nation-building, urging young people to contribute to the country's progress. Meanwhile, Sundar Raju, Principal of Atria Institute of Technology, delivered the presidential address, underscoring the institute's commitment to fostering innovation and excellence.

The event saw PESITM Shivamoga securing the overall championship title, while Atria Institute of Technology and AJITM shared the runner-up position. The program concluded with the rendition of the national anthem, "Vande Mataram."

The inauguration on May 24th was presided over by C. S. Sunder Raju, Chairman of Atria Group, Bengaluru. Prof. Deepak Kumar Srivastava, Vice Chairman of the University Grants Commission (UGC), was the chief guest, joined by Manu Saale, MD and CEO of Mercedes-Benz Research and Development India, Dr. S. Vidyashankar, Vice Chancellor of Visvesvaraya Technological University, Belagavi and Ashish Chauhan, National Organizing Secretary of ABVP.

Prof. Srivastava spoke about innovations in India's solar power generation and AI technology, motivating

students to embrace creative learning . Ashish Chauhan inspired students with the slogan "Vande Mataram," encouraging them to make Srishti 2024 a success and share their startup ideas. Ashish Chauhan also encourages the students saying that this is the ultimate platform for meritorious students to unleash their credibility and every student should focus on this.

Manu Saale praised Prime Minister Narendra Modi's visionary leadership and urged students to think ambitiously to tackle global challenges like climate change. Dr. S. Vidyashankar welcomed the guests and highlighted the event's purpose of providing opportunities for students to contribute to India's development through technology and new skills.

C. S. Sunder Raju emphasized the importance of industry engagement and project-based learning, wishing success to Srishti 2024 and inspiring students to pursue diligence in their academic endeavors. Event's inauguration concluded with keynote addresses and a vote of thanks delivered by Dr. Rajesha S, Principal , Atria Institute of Technology.

Throughout Srishti 2024, various competitions, including the project exhibition "Srishti Innovator" and "Avishkar," captivated participants and attendees, culminating in a grand closing ceremony. The event not only celebrated technological innovation but also reinforced the commitment of educational institutions towards fostering a culture of excellence and advancement. ■

(Rashtriya Chhatrashakti Team)

I असम I

अभाविप ने शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की गुवाहाटी विश्वविद्यालय इकाई ने असम के शिक्षा मंत्री डा. रनोज पेगु को एक ज्ञापन देकर असम सरकार की 'प्रज्ञान भारती योजना' के तहत छात्रों से लिए गए प्रवेश शुल्क को विश्वविद्यालय से वापस कराने की मांग की। शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपने के दौरान अभाविप की प्रांत सह मंत्री एवं गुवाहाटी विश्वविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यूनियन की सह सचिव निहारिका देवी, गुवाहाटी महानगर मंत्री स्वप्निल हालोई सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

जानकारी हो कि असम सरकार ने दो लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के छात्रों को मुफ्त प्रवेश देने के लिए प्रज्ञान भारती नामक एक महत्वाकांक्षी योजना घोषित की थी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना की जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को भी दी गई। योजना से जुडी अधिसूचना जारी होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को आश्वासन दिया था कि उनसे प्रवेश के समय लिया गया शुल्क वापस कर दिया जाएगा, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में उचित कदम नहीं उठाया। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय के छात्रावासों में रहने वाले अनेक छात्र-छात्राओं को नियमित रूप में सरकार से मिलने वाली छात्रावास मेस का शुल्क भी नहीं मिला है। इससे छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

स्नातक छात्र की निर्मम हत्या के विरोध में अभाविप का प्रदर्शन

देश भर में धरना-प्रदर्शन कर वामपंथी छात्र संगठन के पुतले फूंके

पटना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बिहार नेशनल कॉलेज में पढ़ने वाले स्नातक के छात्र हर्षराज की निर्मम हत्या पर आक्रोश व्यक्त करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने कहा है कि कॉलेज परिसर में हुई घटना विश्वविद्यालय प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ी करती है। वामपंथी छात्र संगठन आइसा की निंदा करते हुए अभाविप ने प्रकरण की निष्पक्ष जांच करा संलिप्त सभी दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की मांग की है।

जानकारी हो कि गत 27 मई को पटना विश्वविद्यालय के छात्र हर्षराज की हत्या वामपंथी छात्र संगठन 'आइसा' के गुंडों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में कर दी गई थी। घटना के विरोध में अभाविप ने राज्य के विभिन्न जिलों सहित दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू), जवाहलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित देश के अलग-अलग शैक्षणिक संस्थानों में धरना प्रदर्शन किया और दोषियों को गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई की मांग की।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि छात्र हर्षराज की हत्या का कृत्य अत्यंत दुःखदाई एवं निंदनीय है। पटना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेज छात्रावासों का वातावरण अपराधियों से भयभीत करने वाला है। पटना विश्वविद्यालय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्रावासों में अपराध जगत से जुड़े लोग न रहने पाए। हिंसा के वातावरण से शिक्षण कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विश्वविद्यालय की शुचिता को समृद्ध करने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की है।

घटना की निंदा करते हुए दक्षिण बिहार प्रांत मंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। पटना विश्वविद्यालय की लगातार बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर अभाविप ने विश्वविद्यालय प्रशासन को कई बार ज्ञापन भी दिया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया। अभाविप छात्र हर्षराज की हत्या में शामिल सभी अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार कर सजा की मांग करती है, साथ ही दुख की घड़ी में अभाविप की संवेदनाएं दुःख संतप्त परिवार के साथ हैं।

परिजनों से मिले राष्ट्रीय महामंत्री

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने वैशाली जिले के

लालगंज स्थित मृतक हर्ष राज के पैतृक निवास पर परिवारजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने बताया कि अभाविप देशभर में #JusticeForHarsh की मांग को लेकर प्रदर्शनरत है और दोषियों को कठोरतम सजा देने की मांग करती है। साथ ही देश के शैक्षणिक परिसरों को हिंसामुक्त बनाए रखने और सुरक्षित वातावरण के निर्माण हेतु विद्यार्थियों से वामपंथी छात्र संगठनों का पूर्ण बहिष्कार करने का आग्रह भी करती है।

आइसा का पुतला फूंका

राजधानी दिल्ली में अभाविप ने दिल्ली विश्वविद्यालय तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वामपंथी छात्र संगठन 'आइसा' का पुतला दहन कर जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया और घटना में संलिप्त सभी अपराधियों पर जल्द से जल्द कठोरतम कार्रवाई करने की मांग की। अभाविप दिल्ली के प्रदेश मंत्री हर्ष अत्री ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय के होनहार छात्र हर्षराज की आइसा के गुंडों द्वारा निर्मम तरीके से हत्या दुखद है। वामपंथियों ने हमेशा से शैक्षणिक परिसरों को दूषित करने का प्रयास किया है। इस हिंसक एवं अराजक तत्वों से युक्त छात्र संगठन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साबरमती ढाबा पर भी आइसा का पुतला जलाया। प्रदर्शन के दौरान अभाविप कार्यकर्ताओं ने "सुरक्षित एवं हिंसा रहित कैंपस" की मांग की। अभाविप जेएनयू के अध्यक्ष राजेश्वर दुबे ने कहा कि विश्विद्यालय कैंपस सुरक्षित और हिंसा मुक्त होने चाहिए। जेएनयू इकाई मंत्री शिखा स्वराज ने कहा कि आइसा जैसे वामपंथी संगठनों ने शैक्षिक परिसरों में हमेशा ही चर्चा एवं विमर्श के अवसरों का गला घोटते हुए हिंसात्मक कार्यप्रणाली को बढ़ावा दिया है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

शिक्षा से ही होगा देश का पूर्ण विकास : प्रफुल्ल आकांत

प्रांत में अवस्थित गुमला जिले के एक छोटे से प्रखंड सिसई में सिनगी दई कोचिंग सेंटर का उद्घाटन समारोह धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डेक्सटेरिटी ग्लोबल के संस्थापक शरद विवेक सागर एवं मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकान्त के साथ ही सिनगी दई बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष प्रो. नाथू गाड़ी, उपाध्यक्ष सोमनाथ भगत, अभाविप झारखंड बिहार के क्षेत्रीय संगठन मंत्री निखिल रंजन, प्रांत संगठन मंत्री राजीव रंजन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के प्रबंधक गणेश कूड़े, रोमा तिर्की, करुणामय पटबंधा और सुश्री विनीता इंदवार उपस्थित रहे।

गत 21 मई को समारोह में उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि शरद विवेक सागर ने कहा कि राज्य के एक छोटे से कोने से कितनी सुंदर सी पहल हुई हैं। जिस प्रकार हम सब बिजली को विकास से जोड़कर देखते हैं, आज उसी तरह आज यह केंद्र सामने आया है, जहां छोटे बच्चे रहेंगे। यहां बच्चों को खेलकूद के साथ शिक्षण एवं जो संस्कार मिलेंगे, वह उनकी जीवन को रोशन करेगा। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि हमें आगे बढ़ते समय सभी को साथ में लेकर बढ़ना होगा, तभी विकास की रोशनी से हर घर रोशन होगा।

समारोह में अभाविप के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत ने विद्यार्थियों को संकल्प कराया कि वह शिक्षा ग्रहण कर आगे बढ़ेंगे। कितनी भी बाधा या कितनी भी कठिनाई हो, लेकिन शिक्षा ग्रहण करके ही आगे बढ़ेंगे। अभाविप का उद्देश्य यह नहीं है कि विद्यार्थी नवोदय विद्यालय और एकलव्य मॉडल के स्कूलों में शिक्षा लें, बल्कि ऐसे विद्यालयों में पढ़ने के साथ-साथ समाज के उन अनेकों विद्यार्थियों को भी आगे बढ़ाना है, जिनके सामने कठिनाईयां हैं।

जनजाति समाज की शक्ति को स्मरण करते हुए श्री आकांत ने कहा कि यह कोचिंग सेंटर ग्रामीण बहुल क्षेत्र में स्थित है और यहां पढ़ने वाले विद्यार्थी भी ऐसे ग्रामीण परिवारों से आते हैं, जो मेहनत-मजदूरी करके कठिनाईयों के साथ जीवनयापन करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि अलग-अलग कार्य करने वाले सभी लोग मिलकर एक

फाइल फोटो

संगठित समाज का निर्माण करें। भारत की ताकत ग्रामीण समाज है और संगठित समाज से ही देश संगठित होकर विकास के पथ पर बढ़ता रहेगा।

समारोह के दौरान प्रफुल्ल आकान्त और शरद विवेक सागर ने कोचिंग में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों से बातचीत की और उन्हें ट्रैकसूट भी दिए। कार्यक्रम में सभी विद्यार्थियों के अभिभावक, बैजनाथ जालान महाविद्यालय के विद्यार्थी तथा अपने अभाविप कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

जानकारी हो कि सिनगी दई जनजातीय समाज की नारी शक्ति और एकता का प्रतीक है। सिनगी दई उस वीरांगना का नाम है, जिसने पुरुष वेश धारण करके अपनी महिला सेना के साथ उरांव समाज की रक्षा के लिए तीन बार मुगल सेना से युद्ध किया और उन्हें परास्त किया। इसी वीरांगना के नाम पर सिनगी दई बहुउद्देशीय संस्था का गठन किया गया है। यह संस्था राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्रावास, कृषि विकास एवं नर्सरी, महिला एवं युवा रोजगार, पशुपालन पर जोर, जैविक खेती एवं मोटे अनाज का उत्पादन, कौशल प्रशिक्षण, त्यौहार आधारित संस्कृति संरक्षण हेतु कार्य, परम्परागत पूजा पद्धति के संरक्षण हेतु कार्य, खेल गतिविधि, सांस्कृतिक गतिविधि, स्वरोजगार, कुटीर उद्योग एवं परम्परागत औषधि ज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रही है। सिनगी दई कोचिंग सेंटर के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का कार्य किया जाएगा, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। संस्था उत्कृष्ट विद्यार्थियों को चयनित कर उन्हें विभिन्न प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षा की तैयारियों में भी अपनी मदद प्रदान करेगी। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

कागज-प्लास्टिक मुक्त होगी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक आगामी 6 जून से 9 जून के मध्य गुजरात स्थित सूरत में आयोजित की जा रही है। बैठक में अभाविप के 44 प्रांतों के पांच सौ से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। चार दिवसीय बैठक के दौरान विभिन्न सामाजिक-शैक्षणिक विषयों पर विचार-विमर्श करके प्रस्ताव पारित किए जाएंगे।

जानकारी के अनुसार सूरत नगर में बैठक का आयोजन पर्वत पाटिया स्थित माहेश्वरी भवन किया जा रहा है। बैठक में देशभर से आने वाले प्रतिनिधियों के आवास के लिए माहेश्वरी भवन, सीर्वी समाज भवन और संस्कृति भवन में व्यवस्था की गई है। बैठक से पहले ही अभाविप सूरत महानगर कार्यकर्ताओं ने संपूर्ण व्यवस्थाएं संभाल ली हैं और पूरे नगर को सजाकर स्वागतमय बना दिया है। जानकारी के अनुसार 6 जून को नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन होगा, जिसमें सूरत सहित गुजरात के लगभग दो हजार प्रबुद्ध नागरिक हिस्सा लेंगे। इस नागरिक अभिनंदन समारोह से बैठक की आधिकारिक शुरुआत होगी। अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजशरण शाही एवं राष्ट्रीय महासचिव याज्ञवल्क्य शुक्ल की उपस्थिति में आयोजित होने वाले नागरिक अभिनन्दन समारोह में कई गणमान्य अतिथि हिस्सा लेंगे।

अभाविप कार्यकर्ताओं ने बैठक को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। विशेष यह भी है कि प्रतिनिधियों को संगठन से जुड़ी सामग्री जिस बैग में दी जाएगी, उसे पुरानी एवं इस्तेमाल की गई जींस से बनाया गया है। पुरानी जींस का पुनः सर्जन करके उसे सर्वोत्तम और उपयोगी बनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है।

अभाविप राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक 7 जून को प्रारम्भ होगी। बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत और नेपाल से आने वाले प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। बैठक में परिसर और प्रांत के विभिन्न विषयों पर चर्चा-परिचर्चा के बाद सामाजिक एवं शैक्षणिक विषय पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। साथ ही संपूर्ण वर्ष की गतिविधियों के वार्षिक कैलेंडर को अंतिम रूप भी दिया जाएगा।

सूरत और गुजरात के अभाविप कार्यकर्ताओं ने बैठक को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। विशेष यह भी है कि प्रतिनिधियों को दी जाने संगठन से जुडी सामग्री जिस बैग में दी जाएगी, उसे पुरानी एवं इस्तेमाल की गई जींस से बनाया गया है। पुरानी जींस का पुनः सर्जन करके उसे सर्वोत्तम और उपयोगी बनाया गया है। यह बैग महिला उद्योग के संयुक्त उपक्रम से बना है, जो महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का उत्तम उदाहरण पेश करेगा। इसी तरह प्रतिनिधियों को इथेनॉल पेपर से बनी डायरी दी जाएगी, जो पर्यावरणीय सुरक्षा का एक नमूना होगा। प्रतिनिधियों को गाय के गोबर से बने पृष्ठ से तैयार किया गया परिचय पत्र भी आकर्षण का एक विषय होगा। बैठक में उपयोग होने वाली प्रिंटिंग सामग्री में फ्लेक्स का उपयोग नहीं किया जाएगा और प्लास्टिक के अन्य विकल्पों के उपयोग का आग्रह रखा गया हैं।

बैठक के दौरान एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष, अहिल्याबाई होल्कर की जयंती के 300 वर्ष, स्वामी दयानंद सरस्वती की 220वीं जयंती, गुजरात नवनिर्माण आंदोलन और अभाविप की अखिल भारतीय और गुजरात प्रांत की विविध गतिविधियों को प्रदर्शित करेंगी। सूरत के कार्यकर्ताओं ने रचनात्मक पहलुओं से प्रदर्शनी के लिए व्यापक योजना बनाई है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

...एक नायक का विदा होना

■ मनोज कुमार मिश्र

बिहार में कांग्रेस की सरकार ने 1980 में एक समुदाय को प्रसन्न करने के लिए उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दे दिया। उसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की पहल पर संघर्ष समिति बनी और निर्णायक आंदोलन आरम्भ हुआ। आंदोलन में 9 नवंबर 1980 को पटना में विधानसभा का घेराव करने के लिए प्रदेश भर से छात्र-युवा पटना आए। तत्कालीन समय में वर्तमान झारखंड, बिहार से अलग नहीं हुआ था। हजारों का जुलूस आर. ब्लाक के चौराहे पर जैसे ही पहुंचा, पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, जिससे भगदड़ मची। जमशेदपुर से आने वाले हम जैसे कार्यकर्ताओं में से ज्यादातर पहली बार पटना आए थे। उन्हें पटना के रास्ते नहीं पता थे, लेकिन किसी तरह हम सभी पटना स्टेशन पहुंच पाए। पुलिस लाठी चार्ज के विरोध में बिहार बंद इस तरह सफल रहा कि जैसे पटना शहर में कर्फ्यू लग गया हो। बड़ी संख्या में अभाविप कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, जिससे एक बार फिर से 1974 के बिहार आंदोलन की याद ताजा हो गई।

स्वाभाविक है कि आंदोलन की पूरी तैयारी अभाविप ने की होगी। लेकिन आंदोलन के नेता पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के तत्कालीन सचिव सुशील कुमार मोदी थे। वह न केवल व्यवस्था में थे, बल्कि जब लाठीचार्ज हुआ तो लाठी खाने में भी वह सबसे आगे रहे। उनकी भूमिका असम में विदेशी घुसपैठ से लेकर अनेक आंदोलनों में रही। 1973 में छात्रसंघ चुनाव अभाविप और समाजवादी युवजन सभा ने साथ मिलकर लड़ा था। सुशील कुमार मोदी के साथ लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष बने थे। उन्हीं लालू यादव ने मुख्यमंत्री बनकर जब भारी भ्रष्टाचार किया तो सुशील जी ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका डाल कर बहुचर्चित चारा घोटाले को उजागर किया। वह आजीवन लालू परिवार के भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे, जिसके

स्व. सुशील कुमार मोदी

फाइल फोटो

कारण लालू यादव को सालों जेल में रहना पड़ा। सारा जीवन सार्वजनिक रूप से जीने के बावजूद उन्होंने अपने पर एक दाग नहीं लगने दिया।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के आजीवन स्वयंसेवक रहे सुशील जी गत 13 मई को 72 वर्ष की आयु में परलोकवासी हो गए। संपन्न मारवाड़ी परिवार से आने वाले उनका जीवन सादगी से भरा था। पटना विश्वविद्यालय स्नातक प्रतिष्ठा (वनस्पति विज्ञान) की परीक्षा में वह पूरे विश्वविद्यालय में दूसरे नंबर पर रहे। जयप्रकाश नारायण की अपील पर उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई छोड़ दी। वह 1977 से 1988 तक अभाविप के पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे। 1986 में उनका विवाह केरल की मूल निवासी और मुंबई में रहने वाली जेसी जार्ज से हुआ। विवाह समारोह में देश भर के अनेक दलों के आला नेताओं की मौजूदगी में भाजपा के तत्कालीन वरिष्ठ नेता (बाद में देश के प्रधानमंत्री) अटल बिहारी वाजपेयी ने सुशील कुमार मोदी और उनकी पत्नी से भाजपा में सक्रिय होने का प्रस्ताव रखा था, जिसे स्वीकारने में उन्होंने चार वर्ष का समय लगाया। स्वाभिमानी व्यक्तित्व वाले सुशील मोदी

ने कई व्यवसाय किए, लेकिन संगठन के आग्रह पर उन्होंने 1990 में पटना से विधान सभा चुनाव लड़कर राजनीतिक पारी शुरू की, जो आजीवन चली।

वह विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री, संगठन मंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री और 1983 से 1985 तक महामंत्री के दायित्व पर रहे। आपातकाल में वह जेल में रहे। भाजपा के वह प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव और उपाध्यक्ष के पदों का दायित्व संभालने के साथ ही वह बिहार विधानसभा, विधान परिषद, लोक सभा और आखिर में राज्य सभा के सदस्य भी रहे। बिहार विधान सभा में विपक्ष के नेता के साथ ही वह 2005 से 2013 तक और 2017 से 2020 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रहे। 2011 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कार्यान्वन के लिए गठित देश भर के वित्तमंत्रियों की उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष पद को भी उन्होंने संभाला। अध्ययन-मनन की प्रवृत्ति होने के कारण उन्होंने भविष्य की तैयारी कर ली थी। भविष्य में लिखना-पढ़ना जारी रखने के लिए अपने घर में एक छोटा सा पुस्तकालय भी उन्होंने बनाया था।

स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी ने जो भी दायित्व संभाला, उसके लिए पूरी ईमानदारी से कार्य किया। बिहार की राजनीति में उन्होंने भाजपा को कुछ जातियों की सीमा से बाहर निकालकर पिछड़ों की पार्टी के रूप में पहचान दिलाई। इस प्रयास से उन्होंने नए वर्ग को भी भाजपा से जोड़ा। उनके तरीकों से सहमत होने में संगठन से जुड़े लोगों को काफी समय लगा, लेकिन इस बदली हुई राजनीतिक धारा ने भाजपा के लिए आगामी राह आसान कर दी। वह केवल आदर्श नेता ही नहीं थे, बल्कि वह देश और प्रदेश के नायक थे। उनके करीब आने वाला हर कोई उनसे प्रभावित होता था और अभाविप के हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका अनुसरण किया। ■

पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन पर अभाविप ने व्यक्त किया शोक

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री सुशील कुमार मोदी के असामयिक निधन पर अभाविप ने शोक व्यक्त किया है। अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राजशरण शाही, राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान तथा राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के निमंत्रित सदस्य प्रा. मिलिंद मराठे ने सभी अभाविप कार्यकर्ताओं की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की सद्गति हेतु प्रार्थना की।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा है कि व्यवहारकुशलता, संगठनकर्ता भाव तथा मिलनसार व्यक्तित्व सुशील कुमार मोदी की आजीवन पहचान रहा। पहले प्रखर छात्र नेता, तत्पश्चात राजनीति में आने पर कुशल प्रशासक तक की उनकी यात्रा, देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। देश में कर सुधारों को लागू कराने की दिशा में भी उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है। अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री के निधन पर दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय समेत देश भर के विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

जानकारी हो कि 1968 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बनने वाले सुशील कुमार मोदी 1970 में अभाविप के कार्यकर्ता बने। वह 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव निर्वाचित हुए और 1974 में आपातकाल के विरुद्ध आंदोलन में प्रमुख भूमिका का निर्वहन करते हुए देश में छात्र आंदोलन की एक सशक्त पहचान स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपातकाल के दौरान उन्हें पांच बार गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। देश को आपातकाल की छाया से मुक्त कराने के लिए उन्होंने लगभग दो वर्ष जेल में काटे। 1983 से 1985 तक उन्होंने अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री के दायित्व भी संभाला। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

॥ भावपूर्ण श्रद्धांजलि ॥

स्व. सुशील कुमार मोदी

पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री, अभाविप

जन्म : 5 जनवरी, 1952
स्मृतिशेष : 13 मई, 2024

RNI NO.: DELBIL/2017/73636
DATE OF POSTING: 10-11 JUNE, 2024
DATE OF PUBLISHING: 8 JUNE, 2024

POST OFFICE: NDGPO, NEW DELHI
POSTING REGISTRATION NO. DL(C)-11/1409/2024-26

सूरत में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक की तैयारी